

MR. SPEAKER : The question is about curtailment of trains. If you want to ask about anything else, you may put a separate question.

मतदाता सूचियों में मतदान के लिए पात्र व्यक्तियों के नामों का शामिल न किया जाना

*32. श्री मुल्की राज सैनी : क्या बिचि तथा न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता सूची में बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में निर्वाचन सूची में सभी पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) No, Sir. The electoral rolls were revised with reference to the 1st January, 1970 as the qualifying date. Immediately after the dissolution of the Fourth Lok Sabha the Election Commission also issued two Press notes on 29.12.70 and 14.1.71 informing the public that all eligible persons who had completed the age of 21 years on or before the 1st January, 1970 but who did not find their names entered in the rolls should apply immediately to the concerned Electoral Registration Officers for the inclusion of their names. All such applications which were received upto 5.00 p.m. on 18.1.71 were enquired into and disposed of.

(b) In accordance with the provisions of section 21(2)(b) of the Representation of the People Act, 1950, the electoral roll shall be revised in any year in the prescribed manner by reference to the 'qualifying date' (which means the 1st day of January of the year in which it is revised) if such revision has been directed by the Election Commission. The Commission proposes to carry out a thorough revision of the electoral rolls with the 1st January, 1971 as the qualifying date.

श्री मुल्की राज सैनी : अन्य जनतंत्रीय देशों में प्रठारह साल की आयु के लोगों को भी मत देने का अधिकार दिया गया है लेकिन हमारे

यहां 21 साल की आयु वालों को दिया जाता है। उनमें से भी कुछ को वंचित रखा गया है। जो मशीनरी है वह इतनी कमजोर हो गई है कि दूर दराज के रहने वालों और तंग गलियों में रहने वाले ग्राम आदिमियों के नाम तो दूर रहे, बड़े बड़े नेताओं के नाम भी लिस्ट्स में दर्ज नहीं थे। क्या सरकार इस मशीनरी को ठीक करने के लिए कुछ करने जा रही है ? जहां यह साबित ही जायेगा कि फला क्षेत्र में फला नेता का नाम जो लोक सभा की सदस्यता के लिये खड़ा होना चाहता था, बोटर्स लिस्ट में नहीं था, क्या उनके लिये दोषी कर्मचारी के खिलाफ सरकार एकशन लेने के लिये तैयार है और क्या किसी ऐमे केस में किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई एकशन लिया गया है या किसी को कोई सजा दी गई है ?

SHRI H. R. GOKHALE : After the last election in 1967 when the number of voters was 250 million, in this election the number is 275 million. Therefore there is the continuous process of keeping the voters' list up to date and although the date has elapsed, in view of the mid-term poll the Election Commission extended the date and allowed applications to be made for inclusion or for raising objections. Such applications and statements as were received were examined and investigation was done. Investigators were sent and after the investigation report was received such names were included as were to be included and such names were excluded as merited exclusion. All the precautions were taken. Even then it may be that here and there some voters' names may not have been included. It is largely because either the leaders or the voters themselves were not careful or conscious enough to take them up, to make an application to the Election Commission, etc.

MR. SPEAKER : Should we take up Q. No. 33 and Q. No. 32 together ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान दें।

मुझे खेद है कि बिचि मन्त्री महोदय ने समझा भी नहीं है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न क्या पूछा था। एक तैयार किया हुआ उत्तर ही वह पढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न भ्रमण है जवाब असंग है। आप भागे बहाना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही चलेगी कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : चल रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस तरह से नहीं चलेगी माफ़ करिये।

अध्यक्ष महोदय : 32 और 33 क्या एक साथ ले लिये जायें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो गलतियाँ थी, उनको दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है, इसका जवाब नहीं दिया है।

SHRI H. R. GOKHALE : I have not answered Q. No. 33 yet.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE . I have not put the question yet. May I put it now ?

MR. SPEAKER : That was what I was asking him to do.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I now put the question. Q. No. 33.

मतदाता सूचियों में गलतियाँ

*33. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या बिचि सभ्य न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के हाल ही के मध्यावधि चुनावों के लिये तैयार की गई मतदाता सूचियों में बहुत अधिक गलतियाँ पाई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को अक्षरस्थित रूप से पुनरीक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था ; और

(ग) मतदाता सूचियों में से करजी नामों को निकालने तथा वास्तविक मतदाताओं का नाम उनमें सम्मिलित करने के लिये अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) and (b). No, Sir. The electoral rolls were revised with reference to the 1st January, 1970 as the qualifying date. Immediately after the dissolution of the Fourth Lok-Sabha, the Election Commission also issued two Press Notes on 29.12.70 and 14.1.71 informing the public that all eligible persons who had completed the age of 21 years on or before the 1st January, 1970 but who did not find their names entered in the rolls should apply immediately to the concerned electoral Registration Officers for the inclusion of their names. All such applications, which were received upto 5.00 p.m on 18.1.71 were enquired into and disposed of.

(c) In accordance with the provisions of section 21(2)(b) of the Representation of the People Act, 1950, the electoral roll shall be revised in any year in the prescribed manner by reference to the 'qualifying date' (which means the 1st of January of the year in which it is revised) if such revision has been directed by the Election Commission. The Commission proposes to carry out a thorough revision of the electoral rolls with the 1st January, 1971 as the qualifying date.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आप का ध्यान मन्त्री महोदय के उत्तर की ओर दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रश्न का भाग (ए) है :

"whether it is a fact that there were a large number of discrepancies in the electoral rolls prepared for the recent mid-term elections to Lok-Sabha .."

मन्त्री महोदय कहते हैं :

"No, Sir."

क्या मन्त्री महोदय का ध्यान समाचारपत्रों में सन्पादकों के नाम लिखे गये पत्रों की ओर नहीं गया है, जिन में ये शिकायतें की गई हैं कि सारे देश में लाखों मतदाताओं के नाम इलेक्ट्रल रोल में नहीं थे, जिन मतदाताओं ने 1967 में बोट